



साहेब-बीवी और ऑडियो

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दोनों की ओर से सामने आए आरोपों और बयानों के बीच अब कथित ऑडियो की सत्यता को लेकर भी विवाद तेज हो गया है।

अस्पताल में भर्ती रेखा आर्या ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने इष्ट देव भगवान गोल्लू की कसम खाकर दावा किया कि उनके द्वारा साझा किया गया ऑडियो 100 प्रतिशत सच है। उन्होंने ऑडियो में किसी तरह की बनावट या मिलावट होने से इनकार करते हुए इसे एआई से तैयार किए जाने के दावे को भी खारिज किया। रेखा आर्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में शादी से जुड़े कुछ अहम तथ्यों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, शादी से पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पति गिरधारी लाल साहू पहले से विवाहित हैं। मंत्री ने दावा किया कि बच्चों के होने के बाद उन्हें इस बारे में पता चला।

कहा कि इसके बाद पारिवारिक स्तर पर समझाने-बुझाने की प्रक्रिया चली, लेकिन इस दौरान कुछ गंभीर परिस्थितियां



सामने आईं। उन्होंने अपने पति की ओर से ऑडियो में कही गई बातों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके बीच अब इस तरह का सीधा संवाद नहीं रहता। मंत्री ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कभी वैसी बातें कही हों, जैसी कथित ऑडियो में बताई जा रही हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान गोल्लू

की कसम खाते हुए दावा किया कि उनके द्वारा चलाया गया ऑडियो पूरी तरह सच है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इससे पहले रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू पर उत्पीड़न, मारपीट, जातिसूचक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

इस संबंध में देहरादून के कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई है। रेखा आर्या के आरोपों के बाद उनके पति गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने मंत्री पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए और मुख्यमंत्री से कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति की जांच कराने की मांग की।

गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या की ओर से साझा किए गए कथित ऑडियो की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किए जाने का दावा किया। इसके विपरीत, रेखा आर्या ने ऑडियो को वास्तविक बताते हुए एआई के इस्तेमाल की बात से इनकार किया है।

‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़ा विवाद अब निजी जीवन तक सीमित रहने के बजाय राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हाईप्रोफाइल दंपती के बीच सार्वजनिक रूप से सामने आए विवाद ने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने भी इस प्रकरण को लेकर सरकार की जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है।

राजनीति में नेताओं के निजी जीवन से जुड़े विवाद अक्सर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब मामला सत्ता में बैठे मंत्री और उनसे जुड़े लोगों का हो, तब सवाल केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहते। ऐसे मामलों में सार्वजनिक पद की गरिमा, राजनीतिक



पारदर्शिता और आरोपों की निष्पक्ष जांच जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू से जुड़े विवाद ने भी इसी तरह की बहस को हवा दी है। इस प्रकरण का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की एक मंत्री का नाम जुड़ा है। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिला है और वह भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या

सरकार इस विवाद पर तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगी या मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझकर रह जाएगा?

भाजपा के लिए भी यह प्रकरण असहज स्थिति पैदा कर सकता है। एक ओर पार्टी सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर उसके मंत्री से जुड़े विवाद पर उठने वाले सवालों का जवाब देना उसकी

राजनीतिक जिम्मेदारी है। हालांकि, किसी विवाद में नाम आने या आरोप लगने मात्र से किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए जरूरी है कि आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखा जाए। विपक्ष

◆ रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत
◆ राजनीति की नई परतें, भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा
◆ विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में एक नया मोर्चा भी खुला

के लिए यह मामला सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने का अवसर है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष यह जानना चाहेगा कि संबंधित मामलों में क्या शिकायतें दर्ज हुई हैं, क्या किसी सक्षम एजेंसी ने जांच की है और यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है।

राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता को केवल

बयानबाजी नहीं, ठोस तथ्य भी चाहिए। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी भी केवल विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे आरोपों के संबंध में स्पष्ट और प्रमाण आधारित जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के विवादों का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष सरकार के कामकाज, मंत्रियों की भूमिका और जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में रेखा आर्या से जुड़ा विवाद भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इसे सुशासन और पारदर्शिता के सवालों से जोड़कर उठाए।

हालांकि, इस प्रकरण का चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह आगे सामने आने वाले तथ्यों, संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण

ठंड की दस्तक

प्राप्त जानकारी के अनुसार छिदरवाला निवासी संजय सिंह ने रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपनी मोटरसाईकिल घर के बाहर खड़ी की थी लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसकी मोटरसाईकिल अपने स्थान से गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर उभरे जनाक्रोश और दिल्ली में परिवार के प्रदर्शन के बीच भाजपा ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस इस संवेदनशील प्रकरण को न्याय की मांग से



▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

राजधानी में 'हाईटेक' शासन, गांवों में नेटवर्क का 'अकाल'

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। एक तरफ डिजिटल इंडिया के जरिए देश को तकनीक की ताकत से जोड़ने के दावे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी के जिले में ही 17० गांव नेटवर्क की पहुंच से दूर बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि जब देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिले के इतने गांवों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, तो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की हकीकत क्या होगी? राजधानी में बैठकर तकनीकी विकास की योजनाएं बनाने वाली व्यवस्था के लिए यह स्थिति किसी आईने से कम नहीं, जिसमें विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ दिखाई देती है।

डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिक तक आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सरकारी योजनाओं के आवेदन से लेकर बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रमाणपत्रों तक, आज बहुत कुछ इंटरनेट पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन जिस गांव में मोबाइल नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं है, वहां डिजिटल सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के दावे आखिर किस काम के? तकनीक तभी सशक्तीकरण का माध्यम बन सकती है, जब उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो। अन्यथा डिजिटल क्रांति का लाभ उन लोगों तक सिमटकर रह जाता है, जिनके पास पहले से ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

देहरादून को प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी होने का लाभ मिलता है। यहां शासन-सचिवालय, प्रमुख विभागों के कार्यालय और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार है। स्मार्ट तकनीक, आनलाइन सेवाओं और डिजिटल प्रशासन की बातें भी खूब होती हैं। इसके बावजूद जिले के 17० गांवों के नेटवर्क से दूर होने की जानकारी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है। यह केवल मोबाइल

पर बात करने या इंटरनेट चलाने की सुविधा का मामला नहीं है। नेटवर्क का अभाव ग्रामीणों के जीवन, आजीविका और अवसरों से सीधे जुड़ा है। विद्यार्थियों को आनलाइन अध्ययन सामग्री हासिल करने में परेशानी होती है। युवाओं के लिए नौकरी के आवेदन, प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचनाएं और ऑनलाइन प्रशिक्षण मुश्किल हो जाते हैं। ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन और भुगतान संबंधी सुविधाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

सबसे गंभीर स्थिति आपातकाल में पैदा होती है। किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने, दुर्घटना की सूचना देने या प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद मांगने के लिए संचार बेहद जरूरी है। नेटवर्क नहीं होने पर सूचना पहुंचने में देरी भी जोखिम बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संचार सुविधा से वंचित गांवों के नागरिकों को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है? सरकारें लगातार सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दे रही हैं। इससे कागजी कार्रवाई घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को घर के पास सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है। लेकिन आनलाइन व्यवस्था की पहली शर्त ही इंटरनेट है। यदि गांव में नेटवर्क नहीं है, तो ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए भी कस्बों या शहरों का रुख करना पड़ सकता है। यह स्थिति डिजिटल व्यवस्था की एक बुनियादी कमजोरी उजागर करती है। सेवाओं को ऑनलाइन करना आसान हो सकता है, लेकिन उन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तकनीक के अभाव में नागरिकों को अतिरिक्त समय, पैसा और श्रम खर्च करना पड़े, तो डिजिटल सुविधा का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है।

डिजिटल इंडिया की सफलता का



आकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने सरकारी कार्यालय आनलाइन हो गए या कितनी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध करा दी गईं। असली कसौटी यह है कि कितने गांवों तक भरोसेमंद नेटवर्क पहुंचा और कितने नागरिक बिना अतिरिक्त परेशानी के इन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। नेटवर्क विस्तार में दूरसंचार कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी संचार ढांचा विकसित करने के लिए सरकार की नीतियों, प्रशासनिक समन्वय और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। व्यावसायिक लाभ कम होने के कारण यदि कुछ क्षेत्रों में कंपनियां नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता नहीं देतीं, तो ऐसे गांवों को जोड़ने के लिए प्रभावी सार्वजनिक नीति की आवश्यकता होती है।

सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जिले के इन 17० गांवों की पहचान किन आधारों पर की गई है। इनमें कितने गांव पूरी तरह नेटवर्क विहीन हैं और कितने गांवों में केवल कमजोर या अस्थिर सिग्नल की समस्या है? कितने गांवों में मोबाइल टावर लगाने की योजना स्वीकृत है? कितने प्रस्ताव बजट, भूमि, बिजली अथवा अन्य कारणों से लंबित हैं? और इन सभी गांवों को नेटवर्क से जोड़ने की समयसीमा क्या है? जब तक इन सवालों के जवाब

सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक डिजिटल समावेशन के दावे अधूरे ही रहेंगे। केवल योजनाओं की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए गांववार कार्ययोजना, जिम्मेदार विभागों का निर्धारण और नियमित प्रगति की निगरानी आवश्यक है।

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से अलग हैं। पहाड़ी इलाकों में बस्तियों की दूरी, कठिन भूभाग, मौसम और सीमित आधारभूत ढांचा संचार सेवाओं के विस्तार को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही परिस्थितियां मजबूत संचार व्यवस्था की आवश्यकता को और बढ़ाती हैं। पलायन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इंटरनेट नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सकता है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। आपदा के समय समय पर सूचना पहुंचाने में भी संचार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में नेटवर्क से वंचित गांवों को केवल तकनीकी विकास की सूची में पीछे छोटे क्षेत्रों के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह समान अवसर, नागरिक सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा प्रश्न है। यदि राजधानी के जिले में ही संचार की ऐसी खाई मौजूद है, तो सरकार को इसे

प्राथमिकता के आधार पर दूर करना चाहिए।

डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा, जब तकनीक का लाभ शहरों और गांवों के बीच भेदभाव किए बिना हर नागरिक तक पहुंचे। विकास का अर्थ केवल बड़े शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाना भी है, जहां आज भी लोग सामान्य संचार सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देहरादून जिले के 17० गांवों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए सरकार को समयबद्ध योजना बनानी चाहिए। दूरसंचार कंपनियों के साथ समन्वय, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास, वैकल्पिक संचार तकनीकों का उपयोग और नियमित निगरानी जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही, गांववार स्थिति सार्वजनिक कर यह भी बताना होगा कि नेटवर्क विस्तार में देरी क्यों हो रही है और समस्या का समाधान कब तक होगा।

विडंबना देखिए कि देश डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने का दावा कर रहा है, लेकिन राजधानी के जिले में ही सैकड़ों नहीं तो कम से कम 17० गांवों के नेटवर्क से दूर होने की बात सामने आ रही है। यह आंकड़ा केवल संचार व्यवस्था की कमी नहीं दिखाता, बल्कि विकास की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़ा करता है।

डिजिटल इंडिया का असली इम्तिहान महानगरों के चमकते कार्यालयों या सरकारी प्रस्तुतियों में नहीं, उन गांवों में है जहां मोबाइल पर सिग्नल तलाशना भी चुनौती बना हुआ है। सरकार को यह तय करना होगा कि डिजिटल विकास केवल विज्ञापनों और घोषणाओं तक सीमित रहेगा या वास्तव में गांवों की चौखट तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस गांव तक नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां डिजिटल क्रांति का दावा नहीं, केवल उसका इंतजार पहुंचता है।

14, 15 नवंबर को जुटेगे राष्ट्रीय सम्मेलन में कुमाउनी भाषा के साहित्यकार

अल्मोड़ा (आरएनएस)। कुमाउनी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और विकास को लेकर 18वां राष्ट्रीय कुमाउनी भाषा सम्मेलन 14 और 15 नवंबर को अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा। कुमाउनी भाषा न्यास और %पहरे% कुमाउनी मासिक पत्रिका, अल्मोड़ा की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से कुमाउनी भाषा के लेखक, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी और भाषा प्रेमी हिस्सा लेंगे। अब तक कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में 17 राष्ट्रीय कुमाउनी भाषा सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पिछले वर्ष यह सम्मेलन रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में हुआ था। इस बार सम्मेलन के लिए बिदू कर्नाटक को संयोजक, हयात सिंह बिष्ट को सचिव और आनंद सिंह सौतियाल को कोषाध्यक्ष चुना गया है। सम्मेलन में कुमाउनी भाषा और साहित्य की दशा-दिशा, साहित्य की विभिन्न विधाओं और भाषा के मानक स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों के व्याख्यान और परिचर्चाओं के माध्यम से भाषा के भाषाई विकास तथा भविष्य की रणनीति पर विचार होगा। आयोजक कुमाउनी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के साथ ही इसे स्कूल से कॉलेज तक पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी उठाएंगे। कार्यक्रम में कुमाउनी पुस्तक प्रदर्शनी और राष्ट्रीय कुमाउनी कवि सम्मेलन आयोजित होगा।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन

संवाददाता
देहरादून। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश में ट्रॉमा प्रबंधन से संबंधित कार्यशाला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया।

आज यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश में ट्रॉमा प्रबंधन से संबंधित कार्यशाला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने किया। इस अवसर पर स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून के नर्सिंग विद्यार्थियों एवं नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर ट्रॉमा एवं आपातकालीन देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कार्यशाला में एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों की तत्काल देखभाल, गंभीर चोटों की पहचान, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया तथा समय पर उचित उपचार उपलब्ध कराने



जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं, भूस्खलन, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। ऐसी परिस्थितियों में मरीजों की जान बचाने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को ट्रॉमा प्रबंधन,

आपातकालीन देखभाल एवं दुर्घटना के समय जीवनरक्षक कदम उठाने से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून के संकाय सदस्य दीपक बर्तवाल एवं दिग्विजय कठेत के साथ नर्सिंग विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए अपने व्यावहारिक ज्ञान एवं नैदानिक कौशल को विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर रही।

लोहे के बर्तन में भूलकर भी न पकाएं खाने की ये चीजें!

अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मिट्टी के बर्तनों और लोहे के बर्तनों में खाना पकाएँ और खाएँ, क्योंकि आजकल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तन, जैसे एल्युमीनियम, स्टील, नॉन-स्टिक कुकवेयर जानलेवा हो सकते हैं। नॉन-स्टिक बर्तनों में खाना पकाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है।

आजकल लोग बीमारियों के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि जो लोग स्वस्थ जीवनशैली अपनाना चाहते हैं, वे मिट्टी और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियाँ बरतना बेहद ज़रूरी हो गया है। खासकर, कुछ तरह के खाद्य पदार्थों को लोहे के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए।

इन खाद्य पदार्थों को लोहे की कढ़ाई में न पकाएं :

नींबू, टमाटर, सिरका, दही और खट्टी कढ़ी जैसे अम्लीय चीजें लोहे के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं। इससे न केवल व्यंजन में धातु जैसा स्वाद आ सकता है, बल्कि कुछ मामलों में एलर्जी भी हो सकती है। यदि आप इन व्यंजनों को लोहे के बर्तन में पकाने से बचें।

डेयरी उत्पाद: पनीर, दही और अन्य डेयरी उत्पादों को लोहे के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए। लोहे के साथ मिलने पर इनका स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। इसके अलावा, जब डेयरी उत्पादों को लोहे के बर्तनों में पकाया जाता है, तो उनका रंग खराब हो जाता है और वे देखने में भी अच्छे नहीं लगते।

मछली: मछली परतदार और चिपचिपी बनावट के कारण लोहे के तवे पर चिपक सकते हैं। तेल या मक्खन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यह समस्या आ सकती है, जिससे मछली का स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है। धीमी आंच पर लोहे की कढ़ाई में मछली पकाने से बचना ही बेहतर है।

मिठाइयाँ : भले ही भारतीय मिठाइयाँ कढ़ाई में बनती हों, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कम ही होता है। लोहे के बर्तन में पहले से पके हुए खाने की गंध रह सकती है, जिससे मिठाइयों का स्वाद और खुशबू बदल सकती है।

लोहे की कड़ाही में पका हुआ खाना तुरंत किसी दूसरे कांच या एनामेल के बर्तन में रख दें। कढ़ाई को तेज़ स्क्रबर या बहुत हल्के स्पंज से न रगड़ें। लोहे के बर्तन धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। धोने के तुरंत बाद लोहे के बर्तनों को कपड़े से पोंछ लें। लोहे के बर्तनों को रखने से पहले उन पर सरसों के तेल की एक पतली परत लगाएँ। पके हुए खाने को लोहे के बर्तनों में घंटों तक न रखें, क्योंकि इससे धातु जैसा स्वाद या गंध आ सकती है। बर्तन को जंग लगने से बचाने और उसकी गंध को दूर करने के लिए हमेशा उपयोग के बाद गर्म रहते ही साफ कर लें।

लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसून के दौरान नमी भरे मौसम के कारण लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई महिलाएं परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी लिपस्टिक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। हालांकि, कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को पूरे दिन बरकरार रख सकती हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आपकी लिपस्टिक पूरे दिन तक टिक सकती है।

होंठों को साफ और मुलायम बनाएं: लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाने के लिए सबसे पहले अपने होंठों को साफ और मुलायम बनाएं। इसके लिए आप घर पर ही एक स्क्रब बना सकती हैं। एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच शहद और कुछ बूंदें जैतून का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को होंठों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। इसके बाद होंठों पर मॉइस्चराइजर लगाएं।

लिपलाइनर का उपयोग करें: लिपलाइनर का उपयोग करने से लिपस्टिक फैलने से बचती है और आपके होंठों को एक साफ-सुथरा रूप मिलता है। अपने होंठों के प्राकृतिक आकार के अनुसार लिपलाइनर से अपने होंठों की सीमा को तय करें। इससे लिपस्टिक को सही जगह पर रहने में मदद मिलती है और यह लंबे समय तक टिकी रहती है। लिपलाइनर का उपयोग करके आप अपने होंठों को एक सुंदर और आकर्षक रूप दे सकती हैं, जिससे आपकी लिपस्टिक पूरे दिन तक बरकरार रहती है।

मैट लिपस्टिक चुनें: मानसून के दौरान ऐसी लिपस्टिक चुनें, जिसमें चमक कम हो और मैट फिनिश हो। मैट लिपस्टिक नमी को सहन कर सकती है और लंबे समय तक टिकती है। मैट लिपस्टिक का फॉर्मूला आपके होंठों पर एक हल्की परत बनाता है, जो उसे नमी से बचाता है और पूरे दिन तक टिका रहता है। इसके अलावा मैट लिपस्टिक का रंग भी गहरा होता है, जिससे आपके होंठों को एक आकर्षक रूप मिलता है।

अतिरिक्त नमी को हटाएं: अगर आपके होंठों पर ज्यादा तेल या नमी जमा हो गया है तो उसे हटाने के लिए किसी ऐसे कागज का इस्तेमाल करें जो नमी सोख सके। यह आपके होंठों को ताजा बनाए रखेगा और लिपस्टिक को फैलने से रोकेगा। इस तरीके से आप अपने होंठों को साफ-सुथरा रख सकती हैं और लिपस्टिक की चमक को बनाए रख सकती हैं। यह तरीका खासकर उन दिनों में बहुत फायदेमंद होता है जब मौसम ज्यादा नम होता है।

एसएसपी श्वेता चौबे ने साप्ताहिक परेड व पुलिस लाइन चंबा का किया निरीक्षण

संवाददाता

टिहरी। एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे ने साप्ताहिक परेड व पुलिस लाइन चंबा का निरीक्षण कर अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिये।

आज यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा पुलिस लाइन चंबा का निरीक्षण कर वहां संचालित विभिन्न शाखाओं, उपलब्ध संसाधनों, अभिलेखों, साफ-सफाई एवं विभागीय कार्यप्रणाली का जायजा लिया गया। निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। निरीक्षण के दौरान एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार, पुलिस कैंटीन, परिवहन शाखा, कर्मचारियों की बैरक, नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल तथा परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

उन्होंने विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध संसाधनों, अभिलेखों के रखरखाव, व्यवस्थाओं की स्थिति एवं कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शस्त्रागार के निरीक्षण के दौरान शस्त्रों एवं अन्य संबंधित संसाधनों के सुरक्षित रखरखाव, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण तथा निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही पुलिस लाइन में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने एवं उनकी देखरेख के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

एसएसपी द्वारा पुलिस कैंटीन एवं परिवहन शाखा के कर्मचारियों की बैरक का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई एवं रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने



पुलिसकर्मियों के लिए स्वच्छ, व्यवस्थित एवं सुविधाजनक वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। परिवहन शाखा का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं संसाधनों की स्थिति का अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य किए जाने के महत्व पर जोर दिया गया।

एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा पुलिस लाइन में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान हॉल की व्यवस्थाओं एवं उपयोगिता का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल को विभागीय बैठकों, समीक्षा गोष्ठियों एवं अन्य आवश्यक पुलिस गतिविधियों के लिए उपयोगी बनाए जाने के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा पुलिसकर्मियों के कल्याण एवं उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन

करते हुए आमजन की सुरक्षा एवं सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों के कल्याण, सुविधाओं एवं कार्यस्थल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है, जिससे वे पूर्ण मनोयोग एवं सकारात्मक भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। एसएसपी श्रीमती श्वेता चौबे ने पुलिसकर्मियों को पूर्ण अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभागीय कार्यों में समयबद्धता बनाए रखने, अभिलेखों को अद्यतन रखने, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने तथा सभी शाखाओं में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित रखरखाव, बेहतर प्रबंधन, अनुशासित कार्यसंस्कृति एवं पुलिसकर्मियों का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है। टिहरी पुलिस का उद्देश्य पुलिस व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं एवं सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके।

शब्द सामर्थ्य -059

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. अभिमान, घमंड, अनुमान 4. बादल, मेघ, जलद (सं) 6. अधिकार वाला, अधिकारी 8. गति, सामंजस्य, समा जाना 10. कारावास, जेल 11. जोर, शक्ति, जान, सांस 12. राजाओं के रहने का भवन 15. मालामाल, अमीर, धनवान 18. नाव खेने का यंत्र 20. ‘खन’ ध्वनि उत्पन्न होना,

पायल आदि का शब्द करना 21. मार डाला हुआ, घायल किया हुआ 22. हमेशा, आवाज 23. आग की लपट, ज्वाला 24. झगड़ा, तकरार 25. हीरा।

ऊपर से नीचे

1. दोषी, अपराधी 3. ताश में नौ अंक वाला पत्ता 4. झंडा, पताका 5. गहरा कीचड़, पंक 7. बूंद, अंश 9. मृत्यु के देवता 13.

संसार, दुनिया, जग 14. हुजूर, जनाब, सम्मान सूचक एक शब्द (उ.) 16. सच्चा, धर्मनिष्ठ, ईमानवाला 17. अनूठा, बांका, अनुपम, छैला 18. आश्रय, शरण 19. साधुवाद, प्रशंसा 20. पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत संबंधी अनेक बातें लिखी जाती है, एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग 23. गम, मातम, दुख।

1		3		4		5	
		6	7			8	9
10						11	
			12	13		14	
15	16						17
			18		19		
20					21		
22						23	
24					25		

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 58 का हल

स्मृ	ति		पा	व	क		बे	ल
	र	ज	नी	च	र			दू
मु	स्का	न		न	म	की	न	
सा	र		स			ट	ख	ना
फि		अ	जा	य	ब		रा	जा
र	च	ना		था	ल			य
		धि		र्थ		स	मा	ज
उ	प	कृ	त		आ	वा	ज	
ल्लू		त			ब	ल	रा	म

करण जौहर का कॉफी विद करण के बाद नया धमाका!

कॉफी विद करण का नौवां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा। ये ऐलान खुद करण जौहर ने जियो हॉटस्टार पर कर दिया था, लेकिन क्या एक चैट शो होस्ट के रूप में ये उनका आखिरी सफर है? बिल्कुल नहीं। खबर है कि करण एक बिल्कुल नए चैट शो को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। जब कमान करण के हाथों में है, तो जाहिर है कि इसमें बॉलीवुड का स्टाइल, चमक-धमक और चटपटी खबरों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, करण अपना नया शो लाना चाहते हैं। दरअसल, कॉफी विद करण नाम के अधिकार उनके पास नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार के पास हैं। कहा जा रहा था कि करण फिल्म निर्देशन पर ध्यान देने के लिए ये शो बंद कर रहे हैं, लेकिन असली वजह ये है कि वो पूरी तरह से अपना नया शो बनाना चाहते हैं, जिसे वो पहले यूट्यूब पर रिलीज करेंगे और फिर किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचेंगे। हाल-फिलहाल करण का पूरा ध्यान कॉफी विद करण 9 पर है। इस आखिरी सीजन के लिए उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज सितारों को एक साथ जुटाया है। सूत्रों के मुताबिक, सलमान खान ने गुरुवार को अपने एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। चर्चा है कि शो की शुरुआत या तो सलमान खान करेंगे या फिर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल। यही नहीं, पहली बार शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान भी एक साथ शो में नजर आएंगे।

चार यार सीरीज में दोस्ती और अंडरवर्ल्ड की दिखेगी कहानी

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी नई वेब सीरीज चार यार का ऐलान किया है। यह एक क्राइम ड्रामा है, जिसकी कहानी मुंबई के 4 जिगरी दोस्तों और अंडरवर्ल्ड के दलदल पर आधारित होगी। विनय वायकुल इसके निर्देशक हैं, जिन्हें सीरीज ग्यारह ग्यारह (2024) के लिए जाना जाता है। सीरीज में पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयारक मेहता मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। साई तमहंकर, सिकंदर खेर, दिव्येंद्र भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल सहायक कलाकार होंगे। निर्माताओं ने 8 एपिसोड वाली सीरीज का पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन दिया, चार दोस्त, एक चोरी, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। इसकी कहानी 2000 के दशक में मुंबई पर आधारित होगी, जहां ये चारों दोस्त अप्रत्याशित परिस्थिति में फंसकर गैंगस्टर्स के रास्ते पर आ खड़े होते हैं। उनकी दोस्ती ही उन्हें इस मुश्किल से निकालती है। सीरीज का प्रीमियर 23 अक्टूबर, 2026 से भारत और 24 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर होगा।

आमिर खान लेकर आएंगे कविताएं और आम जनता की अनसुनी कहानियां

सुपरस्टार आमिर खान ने देश के जमीनी हुनरबाजों को एक बड़ा मंच देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म आमिर खान टॉकीज पर एक अनोखा ओपन माइक शो वन्स अपॉन अ माइक शुरू किया है। इसका ऐलान आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा किया गया। इस पहल की शुरुआत मशहूर आर्ट कलेक्टिव कम्पून के सहयोग से की गई है। इसके जरिए उन आवाजों को दर्शकों के सामने लाया जाएगा, जिन्हें मुख्यधारा के मनोरंज में जगह नहीं मिलती। प्रोडक्शन ने घोषणा करते हुए लिखा, यह वो महफिल है जहां कहानियां उड़ान भरेंगी... यहां अलग अंदाज है और उस अंदाज की एक आवाज भी है। इस मंच की खास बात यह होगी कि यहां सिर्फ कविताएं नहीं सुनाई जाएंगी, बल्कि रैप, स्पोकन वर्ड और आम जनता की अनसुनी कहानियों को भी दुनिया के सामने लाया जाएगा। निर्माताओं ने पहला वीडियो भी जारी किया है, जिसकी शुरुआत मुंबई की महिला रैपर सानिया एमक्वू की सच्ची और दमदार कहानी से हुई।

सलमान खान ने लॉन्च किया अपना यूट्यूब चैनल, अब फैस से सीधे जुड़ेंगे अभिनेता

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अब यूट्यूब की दुनिया में भी कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की घोषणा की है। इस खबर से उनके प्रशंसकों में उत्साह है। घोषणा के कुछ ही समय बाद उनके चैनल से 13 हजार से अधिक सदस्य जुड़ गए।

सलमान ने अपने चैनल की घोषणा करते हुए लिखा, शुरू से शुरू करते हैं... मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल। ए से जेड तक सब यहां मिलेगा। साझा किए गए वीडियो में अभिनेता अपने खास और मजेदार अंदाज में अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक का उल्लेख करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रशंसकों को अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी झलकियां दिखाने का वादा किया है। चैनल के परिचय में उन्होंने खुद को फिल्म अभिनेता, कलाकार, चित्रकार और मानवतावादी बताया है। साथ ही इसे अपना आधिकारिक चैनल घोषित किया है। चैनल पर फिलहाल 10 छोटे वीडियो भी मौजूद हैं। हालांकि, प्रशंसकों को अब उनके पहले आधिकारिक व्लॉग यानी वीडियो ब्लॉग या किसी विस्तृत वीडियो का इंतजार है।

सड़क पर गिरी, तब पता चला ब्रेन ट्यूमर है: सबा पटौदी

अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने 27 साल की उम्र में मस्तिष्क के ट्यूमर से जूझने के अपने मुश्किल अनुभव साझा किए हैं। अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सबा ने बताया कि उन्हें बीमारी का कोई शुरुआती लक्षण महसूस नहीं हुआ था। एक दिन अचानक वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ीं। इसके बाद कराई गई चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) जांच में उनके मस्तिष्क के तीसरे निलय में एक संदिग्ध गांठ का पता चला। करीब छह महीने बाद हुई शल्य चिकित्सा में चिकित्सकों ने इसे पायलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा' नामक ट्यूमर के रूप में पहचाना।

सबा ने बीमारी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें पहले से किसी तरह की परेशानी नहीं थी। एक दिन घर से बाहर निकलने पर उन्हें पेट में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। चूंकि उनका पेट पहले से संवेदनशील रहता था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद खाने-पीने की वजह से ऐसा हुआ है।

हालांकि, कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ीं। सबा ने बताया कि पहले भी वह कभी-कभी बेहोशी जैसी स्थिति को रक्तचाप में बदलाव या तेज रोशनी से जोड़कर देखती थीं, लेकिन इस बार अनुभव अलग था।

अचानक असहज महसूस होने पर उन्होंने अपनी दोस्त से घर लौटने के लिए कहा। इसी दौरान उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और वह गिर पड़ीं। होश आने पर उन्होंने खुद को इमारत के बाहर सड़क पर पाया। वह स्थिति को समझ पातीं, उससे पहले ही दोबारा बेहोश हो गईं।

सबा के मुताबिक, पूरी तरह होश में आने में करीब 20 से 25 मिनट लगे। इसके बावजूद उनके सिर में भारीपन बना हुआ था। घटना के बाद चिकित्सकों ने सबा की एमआरआई जांच कराई। इसमें मस्तिष्क के तीसरे निलय में एक संदिग्ध



गांठ दिखाई दी। ट्यूमर की स्थिति को देखते हुए शुरुआती जांच में चिकित्सकों ने इसके कोलॉयड सिस्ट होने की आशंका जताई थी।

इसके बाद करीब छह महीने तक जांच और उपचार की प्रक्रिया चली। अंततः सबा की मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा की गई। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने गांठ की पहचान पायलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा के रूप में की। यह एक प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है, जो आमतौर पर धीमी गति से बढ़ता है।

सबा ने बताया कि महज 27 साल की उम्र में बिना किसी स्पष्ट शुरुआती लक्षण के गंभीर बीमारी का पता चलना उनके लिए बड़ा झटका था। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा की बात सुनकर वह पूरी तरह टूट गई थीं। उन्हें लगने लगा था कि उनकी

जिंदगी रातोंरात बदल गई है।

बीमारी की जानकारी मिलने के बाद वह कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के रोने लगती थीं। इस कठिन दौर में उन्हें सबसे ज्यादा डर अपनी स्वतंत्रता खोने और दूसरों पर निर्भर हो जाने का था। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मनिर्भर बने रहना चाहती थीं।

सबा ने बताया कि शल्य चिकित्सा के दौरान चिकित्सकों ने ट्यूमर को सुरक्षित तरीके से निकालने का प्रयास किया। उनके अनुसार, ट्यूमर मस्तिष्क के उस हिस्से के पास स्थित था, जिसका संबंध अल्पकालिक स्मृति से है। इसलिए ऑपरेशन के दौरान विशेष सावधानी बरतनी जरूरी थी। चिकित्सकों ने जितना संभव हो सका, ट्यूमर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला।

संदीपा धर ने आतिश कपाड़िया को दिया कॉमेडी से परिचय कराने का श्रेय



नेटफ्लिक्स की चुंबक अपने मजेदार किरदारों और हल्के-फुल्के हास्य के कारण दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। शो में संदीपा धर, किरण का किरदार निभा रही हैं, जो बाकी अजीबोगरीब किरदारों के बीच बेहद समझदार हैं।

शो का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए संदीपा ने कहा, एक दिन मुझे चुंबक के निर्देशक आतिश कपाड़िया का

फोन आया और उन्होंने बताया कि वे नेटफ्लिक्स और जेडी के साथ मिलकर एक नया शो बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुझे इसके लिए टेस्ट देने को कहा। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गई कि कॉमेडी और मैं ? क्योंकि मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की थी। लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी। संदीपा ने आगे बताया, इसके बाद जब मेरी मुलाकात आतिश

कपाड़िया से हुई तो उन्होंने जिस अंदाज में मुझे पूरी कहानी सुनाई, वो उससे भी ज्यादा मजेदार था। उन्होंने जिस तरह हर किरदार को खुद निभाकर दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नाटक देख रही हूं। उसी समय मैंने तय कर लिया कि मुझे इस शो का हिस्सा बनना ही है।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए संदीपा धर ने कहा, किरण का किरदार निभाना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वह शो की सबसे समझदार इंसान है। उसे अपने एक्शन से ही कॉमेडी करना था, लेकिन साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना था कि उसके एक्सांस बनावटी न लगें। हालांकि इस बारे में मैंने आतिश से काफी चर्चा भी की थी।

संदीपा की माने तो आतिश कपाड़िया की कहानी सुनाने की शैली और किरदारों को जीवंत करने की उनकी कला ने ही उन्हें चुंबक से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं किरण के रूप में उनका संतुलित और सहज अभिनय शो की खासियत बनकर उभरा है और दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

आरोपों की आग और न्याय का पैमाना

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। आखिर वह कथित वीआइपी कौन था, जिसका नाम लेकर इस मामले में लगातार सवाल उठते रहे हैं? अंकिता के माता-पिता इसी सवाल का जवाब मांग रहे हैं। कथित वीआइपी प्रकरण को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक बहस में उछाला जा रहा है। परिवार उनकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति पर भी आपत्ति जता चुका है। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल है कि क्या राजनीतिक आरोप, जनाक्रोश और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं? जवाब है ही नहीं। आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसकी पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होनी चाहिए।

इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि अंकिता के परिवार के मन में कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर सवाल हैं, यदि वह जांच की मांग कर रहे हैं और यदि सार्वजनिक जीवन में इस मामले को लेकर अविश्वास बना हुआ है, तो उन सवालों का जवाब देना सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। केवल आरोपों को खारिज कर देने या राजनीतिक विवाद बताकर किनारे कर देने से संदेह समाप्त नहीं होते। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। वनंतरा

रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की हत्या के मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को अदालत ने दोषी ठहराया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव था। लेकिन कथित वीआइपी की भूमिका को लेकर उठते सवालों ने मामले को राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में बनाए रखा। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि इस पहलू की निष्पक्ष जांच हो और उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए।

यहीं सरकार और जांच एजेंसियों की जवाबदेही सामने आती है। यदि किसी आरोप के समर्थन में साक्ष्य हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तो उसके कारण और निष्कर्ष भी स्पष्ट होने चाहिए। जनता को न तो अफवाहों के भरोसे छोड़ा जा सकता है और न ही गंभीर सवालों के जवाब के बिना चुप रहने की अपेक्षा की जा सकती है। कथित वीआइपी प्रकरण में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम राजनीतिक आरोपों और सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आया है।

उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें अंकिता हत्याकांड का वीआइपी या दुष्कर्मी घोषित करना उचित नहीं है। ऐसा कोई निष्कर्ष न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आरोपों से जुड़े सवाल पूछना गलत है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की



निष्पक्ष जांच की मांग और उसे अपराधी घोषित करना दो अलग बातें हैं। पहली लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है, जबकि दूसरी के लिए विश्वसनीय साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है।

सरकार की असली परीक्षा यह नहीं कि वह आरोपों को कितनी दृढ़ता से खारिज करती है, बल्कि यह है कि वह निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है। अंकिता के माता-पिता का दिल्ली जाकर धरना देना और न्याय की मांग करना इस बात का संकेत है कि वह मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। इंडिया गेट पर धरने के दौरान उनके हिरासत में लिए जाने की घटना ने भी राजनीतिक विवाद को हवा दी। लेकिन किसी पीड़ित परिवार के सवालों का समाधान उसे धरनास्थल से हटाने भर से नहीं हो सकता। प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, पर उसके साथ यह जिम्मेदारी भी है कि शिकायतों और मांगों पर उचित कार्रवाई हो।

यहां सरकार को स्पष्ट करना चाहिए

कि कथित वीआइपी की भूमिका से संबंधित शिकायतों की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन-से पहलू जांच के दायरे में हैं और परिवार को उपलब्ध कानूनी विकल्पों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। यदि किसी मांग पर कार्रवाई संभव नहीं है, तो उसका कारण भी तथ्यों और कानून के आधार पर बताया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में महिला सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है। इसलिए कथित वीआइपी प्रकरण पर उठने वाले सवालों का राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि भाजपा अपनी सरकार की कार्रवाई और दोषियों को मिली सजा का हवाला दे रही है।

लेकिन इस राजनीतिक टकराव में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अंकिता का परिवार है। उसे राजनीतिक दलों के बयानों से अधिक तथ्य चाहिए। उसे यह जानना है कि उसके सवालों की जांच हुई या नहीं, उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण हुआ या नहीं और जांच एजेंसियों ने किन निष्कर्षों पर पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। यदि सरकार को लगता है कि जांच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, तो उसे तथ्यों के साथ अपनी स्थिति रखनी चाहिए। यदि कोई पहलू अब भी जांच की मांग करता है, तो उसकी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता जरूरी है।

न्यायालय साक्ष्यों और कानून के आधार पर निर्णय देता है। जनता का आक्रोश अपने आप में दोषसिद्धि का

प्रमाण नहीं है। लेकिन जनता का अविश्वास भी ऐसा प्रश्न है जिसे सरकार और संस्थाएं अनदेखा नहीं कर सकतीं। कानून का शासन तभी मजबूत होता है, जब न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसके बारे में लोगों को विश्वसनीय जानकारी मिले। अंकिता हत्याकांड में दोषियों को सजा मिलना और कथित वीआइपी से जुड़े सवालों का समाधान होना अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक मामले में हुई दोषसिद्धि को दूसरे पहलू पर उठे हर सवाल का अंतिम उत्तर न मान लिया जाए। अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर किसी को बिना प्रमाण अपराधी घोषित करना भी गलत है और प्रभावशाली लोगों से जुड़े सवालों को बिना जवाब दिए छोड़ देना भी।

सरकार को चाहिए कि वह राजनीतिक बचाव की मुद्रा से बाहर निकले और जांच की स्थिति पर स्पष्टता दे। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वह प्रत्येक प्रासंगिक साक्ष्य की निष्पक्षता से पड़ताल करें और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह पीड़ित परिवार के दुख को अपने राजनीतिक लाभ का साधन बनाने के बजाय न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दें। अंकिता के माता-पिता को जवाब चाहिए, जनता को पारदर्शिता चाहिए और लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें न किसी को बिना सबूत दोषी ठहराया जाए, न किसी को उसके पद या प्रभाव के कारण सवालों से परे माना जाए। यही इस मामले की सबसे बड़ी कसौटी है।

सू- दोकू क्र.059

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

सू-दोकू क्र.58 का हल

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।

2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।

3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

एसपी ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण

हमारे संवाददाता
उत्तरकाशी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमलेश उपाध्याय द्वारा कोतवाली बड़कोट का औचक निरीक्षण कर कोतवाली परिसर की साफ-सफाई, पुलिस व्यवस्थाओं, अभिलेखों एवं विभिन्न पत्रावलियों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव तथा पुलिस कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनशिकायतों एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने, सीसीटीएनएस कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने तथा सभी ऑनलाइन पोर्टल एवं अभिलेखों को अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कोतवाली में आने वाले आगंतुकों, पीड़ितों एवं आमजन के साथ विनम्र, संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने पर विशेष जोर दिया।

त्योहारी सीजन के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अराजक तत्वों, अवैध नशे के कारोबार तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित चेकिंग, निगरानी एवं आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को



कहा।

कोतवाली परिसर में नवनिर्मित/निर्माणाधीन बैरक का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की जानकारी ली गई। उन्होंने निर्माण कार्यों में उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोतवाली बड़कोट के नए भवन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण करते हुए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पत्रावलियों एवं आवश्यक पत्राचार की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह 2.0 के अंतर्गत आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साइबर अपराधों के नए तरीकों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव तथा साइबर सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट चंचल शर्मा, प्रभारी निरीक्षक बड़कोट सुभाष चंद्र, वरिष्ठ उ.नि. रणवीर चौहान, यातायात उ.नि. विरेन्द्र पंवार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

कानून व्यवस्था पर शर्मा ने सरकार को घेरा

◆बोले महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण हो सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने प्रदेश में सामने आ रही गंभीर आपराधिक घटनाओं और घरेलू हिंसा के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अपराधों की रोकथाम, महिलाओं की सुरक्षा और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

लालचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण वातावरण, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी है। ऐसे में जब प्रदेश में गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, तो सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कानून व्यवस्था केवल दावों से मजबूत नहीं होती, बल्कि इसके लिए धरातल पर प्रभावी कार्रवाई और आम जनता के बीच सुरक्षा का विश्वास कायम करना जरूरी है।

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की ओर से अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता को सामने लाता है। शर्मा ने कहा कि राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र की विष्णुलोक कॉलोनी में 6 अक्टूबर 2026 को सामने आया तिहरा हत्याकांड भी गंभीर चिंता का विषय है। शर्मा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों और घरेलू हिंसा की घटनाओं को नागरिकों के लिए चिंता का विषय बताया है। उनका कहना है कि सरकार को कानून व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए।

एक साल से फरार दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाददाता

टिहरी। नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक साल से फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुनि की रेती एवं देवप्रयाग पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मिली सूचना एवं सुरागरसी-पतारसी के आधार पर वारंटी सुनील चौहान पुत्र लल्लन चौहान, निवासी शिवाजी नगर, ऋषिकेश, जनपद देहरादून, मूल निवासी: ग्राम हालपुर, थाना बासडी, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश को नटराज चौक से गिरफ्तार किया। थाना देवप्रयाग पर पंजीकृत मुकदमें एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रहे नसीम पुत्र असगर, निवासी ग्राम मुस्तफाबाद पदार्थ, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार, को मिली सूचना पर पुलिस टीम ने होली चौक, जनपद हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

‘मियां-बीवी’ के विवाद में घिरी ‘सत्ता’ ... ◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

और सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। केवल विवाद के आधार पर किसी राजनीतिक दल को नुकसान या लाभ होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। यदि भ्रष्टाचार से संबंधित कोई ठोस शिकायत या प्रमाण मौजूद है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं, तो तथ्यों के आधार पर उनका खंडन किया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में न तो किसी मंत्री को आरोपों से परे माना जा सकता है और न ही किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराया जा सकता है। जनता को इस विवाद में राजनीतिक शोर से अधिक स्पष्टता, प्रमाण और जवाब चाहिए। रेखा आर्या-गिरधारी लाल साहू प्रकरण अब इसी कसौटी पर सरकार और विपक्ष, दोनों की भूमिका को परखने का विषय बन गया है।

भाजपा ने कांग्रेस को घेरा.. ◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

का दोबारा राजनीतिक केंद्र में आना भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इस मामले के जरिए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये को मुद्दा बनाकर पलटवार कर रही है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तीखा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से परे जनता की अपेक्षा स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा के सवाल पर दोहरे मानदंड न हों, गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय की मांग के लिए बार-बार संघर्ष न करना पड़े। अंकिता के नाम पर चल रही इस सियासी लड़ाई में राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता भी इसी कसौटी पर परखी जाएगी।

रामलीला महोत्सव-2026: छठे दिवस पर शूर्पणखा लीला और सीता हरण का भव्य मंचन

◆डिजिटल चिंगारियों और आधुनिक तकनीक ने रचा अलौकिक दृश्य संसार

हमारे संवाददाता

देहरादून। रेसकोर्स स्थित श्री गुरु नानक मैदान में श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी द्वारा आयोजित उत्तराखंड की ऐतिहासिक भव्य रामलीला महोत्सव-2026 के छठे दिवस को ‘धर्म शक्ति दिवस’ के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शूर्पणखा लीला और सीता हरण का भव्य मंचन किया गया। आकाश मार्ग में पुष्पक विमान और आधुनिक लेजर तकनीक के माध्यम से रावण-जटायु के महासंग्राम का रोमांचक दृश्य प्रस्तुत किया गया। वहीं, डिजिटल लेजर वॉल से बनी लक्ष्मण रेखा और उसे पार करने के प्रयास में रावण के स्पर्श से निकली डिजिटल चिंगारियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

‘धर्म शक्ति दिवस’ पर श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून द्वारा सनातन संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख श्री श्री 108 महंत कृष्णगिरी महाराज जी तथा श्री गंगा सभा, हरकी पैड़ी, हरिद्वार के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ को सम्मानित किया गया।



मुख्य अतिथि श्री गुरदीप सिंह सपपल ने कहा कि यह रामलीला धार्मिक सद्भाव एवं सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है, जिसे वर्ष 2025 में 82 लाख से अधिक लोगों ने देखा और यह उत्तराखंड की सबसे अधिक देखी जाने वाली रामलीला बनी। टपकेश्वर के महंत श्री श्री 108 कृष्णा गिरी जी महाराज ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से सनातन परंपराओं का संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि वर्ष 1952 से पुरानी टिहरी

में चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला आज देहरादून में नई ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। लेजर और डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारंपरिक प्रसंगों को नई पीढ़ी के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुरदीप सिंह सपपल, टपकेश्वर के महंत श्री श्री 108 कृष्णा गिरी जी महाराज, श्री गंगा सभा, हरकी पैड़ी, हरिद्वार के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, मधुबन ग्रुप ऑफ होटल्स के हेमंत कोच्कर, श्री हनुमान चालीसा समूह की अध्यक्ष सारिका चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे।

चरस व स्मैक के साथ दो लोग गिरफ्तार

देहरादून (सं)। पुलिस ने चरस व स्मैक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आईडीपीएल गोल चक्कर के पास दो लोगों को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उनको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उनको थोड़ी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से 131 ग्राम चरस व 6 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पृष्ठताछ में उन्होंने अपने नाम हिमांशु जाटव पुत्र मनोज जाटव व सतीश कुमार पुत्र कलीराम निवासी शांतिनगर बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

सड़क सुधार कार्यों की पड़ताल करने मैदान में उतरे सचिव लोक निर्माण विभाग

संवाददाता

देहरादून। सचिव, लोक निर्माण विभाग, पंकज कुमार पांडेय तड़के सुबह 6 बजे से देहरादून शहर के प्रमुख मार्गों एवं स्थलों के स्थलीय निरीक्षण पर निकले।

आज यहां मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने तथा सड़क सुधार कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन पंकज कुमार पांडेय तड़के सुबह 6 बजे से देहरादून शहर के प्रमुख मार्गों एवं स्थलों के स्थलीय निरीक्षण पर निकले। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया तथा सड़क सुधार एवं गड्ढा भरण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सचिव लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी सड़कों को 18 अक्टूबर 2026 तक गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागीय अधिकारी पूरी गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने सड़क सुधार कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को



पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6 बजे कालीदास रोड टर्न से हुई। इसके बाद सचिव ने कैनाल रोड, नागल, मसूरी डायवर्जन, सहस्रधारा तिराहा, लाडपुर, जोगीवाला, रिस्यना पुल, घंटाघर, चकराता रोड एवं गढ़ी कैंट सहित देहरादून शहर के प्रमुख मार्गों एवं स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मार्गों की स्थिति का जायजा लेते हुए सड़क सुधार कार्यों की प्रगति का आकलन किया। प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आध

ार पर सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को आवागमन में सुविधा मिले और सड़क सुरक्षा को भी बेहतर बनाया जा सके। लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों को निर्धारित समयसीमा में गड्ढामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सड़क सुधार कार्यों की निगरानी और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार, मुख्य अभियंता दयानंद, अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, अधीक्षण अभियंता अरुण पांडेय, अधिशासी अभियंता बी.एन. द्विवेदी सहित अभियंता प्रवीण कुश, दीपक, सुरेश तोमर, विपुल सैमी तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री से जुड़े 210 करोड़ की अवैध संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो

हमारे संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य से जुड़े उनके पति गिरधारी लाल साहू द्वारा लगाए गए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने के कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधिवक्ता एवं कानूनराज के संस्थापक पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखंड में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच एवं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को जारी एक वीडियो में श्रीमती रेखा आर्य के पास लगभग 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति होने का आरोप लगाया गया है। इस सार्वजनिक रूप से सामने आए आरोप की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने संबंधित जांच एजेंसी से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि जब किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति से संबंधित इतनी बड़ी राशि की कथित संपत्ति का मामला सार्वजनिक होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होना



◆अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने की सतर्कता अधिष्ठान में जांच की मांग

जनहित में आवश्यक है। हालांकि, केवल किसी वीडियो में आरोप लगाए जाने से आरोपों की सत्यता सिद्ध नहीं होती। इसलिए संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जानी चाहिए।

शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित व्यक्तियों की चल-अचल संपत्तियों, आय के ज्ञात एवं वैध स्रोतों, निवेश, बैंक खातों, एफडी, शेयरों, कंपनियों तथा अन्य वित्तीय हितों से संबंधित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण किया जाए। साथ ही, यह भी जांच की जाए कि संबंधित संपत्तियां वैध आय के स्रोतों से अर्जित की गई हैं अथवा नहीं और

उनके संबंध में आवश्यक वैधानिक घोषणाएं एवं विवरण प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं।

शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(इ) एवं 13(2) का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि जांच में संबंधित कानूनी प्रावधानों के आवश्यक तत्व और अपराध के पर्याप्त आधार सामने आते हैं, तो नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

पंकज सिंह क्षेत्री ने यह भी मांग की है कि जांच ऐसे सक्षम अधिकारी से कराई जाए, जिस पर किसी प्रकार के अनुचित दबाव या पक्षपात की आशंका न हो। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए तथा निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर निकाले जाएं। अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान से शिकायत पर विधिवत संज्ञान लेकर प्रारंभिक जांच करने, उपलब्ध वीडियो एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उनके साथ अल्का शर्मा एडवोकेट, अजय धीमान एडवोकेट मौजूद थे।

अकिता भण्डारी को न्याय दिलाने की माँग पर उक्रांद का प्रदर्शन

हमारे संवाददाता

देहरादून। अकिता भण्डारी हत्याकांड में न्याय की माँग तथा दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (उक्रांद), महानगर देहरादून ने आज द्रोण चौक पर भाजपा सरकार एवं दुष्यंत गौतम का पुतला दहन कर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान दल के पदाधिकारियों ने सीबीआई जाँच में तेजी लाने, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच करने और दोषियों को सजा दिलाने की माँग उठाई।

केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि अकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई जाँच को लटकाए जाने की आशंका से जनता में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच शीघ्र पूरी कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। इसी माँग को लेकर उत्तराखण्ड क्रान्ति दल आगामी 24 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय का घेराव करेगा। महानगर अध्यक्ष प्रवीण चन्द रमोला ने सवाल उठाया कि अकिता भण्डारी प्रकरण की सीबीआई जाँच पूरी होने से पहले दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने का निर्णय क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को लेकर उठ रहे सवालों पर संबंधित पक्षों को स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि जाँच की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कायम रहे। केंद्रीय महामंत्री राजेन्द्र बिष्ट ने माँग की कि अकिता भण्डारी प्रकरण की सीबीआई जाँच शीघ्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि जाँच की स्थिति से संबंधित वैधानिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के निर्णय पर उठ रहे सवालों का भी स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।



◆भाजपा सरकार और दुष्यंत गौतम का पुतला दहन

एक नवम्बर को निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। सत्य साईं सेवा संगठन के कर्नल योगेन्द्र सिंह ने बताया कि एक नवम्बर को संगठन की तरफ से साईं ग्रेस एकेडमी इंटरनेशन रायपुर रोड में निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहा है।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल योगेन्द्र सिंह ने कहा कि सत्य साईं सेवा संगठन उत्तराखण्ड का मूल उद्देश्य मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। संगठन मानव सेवा ही माधव सेवा के आदर्श को आत्मसात करते हुए विभिन्न सामाजिक, जलकल्याणकारी और सेवा गतिविधियों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना समाज और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सेवा पहुंचाना संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है। निःशुल्क हृदय रोग चिकित्सा शिविर भी इसी भावना का हिस्सा है। संगठन का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और प्रारंभिक चिकित्साकीय परामर्श प्राप्त करने में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि शिविर में मुख्य सुविधाएं हृदय रोगों की जांच, प्रारंभिक स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और आगे के उपचार संबंधी मार्गदर्शन शुल्क शिविर में उपलब्ध जांच एवं परामर्श सम्बन्धी निःशुल्क सुविधाएं हैं।

नूडल्स खाकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत!

संवाददाता

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली और बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग या किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो



सकेगी।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, परिवार रात में नूडल्स खाने के बाद सोने चला गया था। शनिवार सुबह जब घर से कोई हलचल नहीं हुई और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। जब पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो पूरा परिवार बेड पर अचेत पड़ा हुआ था। उन्हें जगाने की कोशिश की गई लेकिन किसी

के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय महेश, उनकी 36 वर्षीया पत्नी ललिता और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने रसोईघर से चाय के बर्तन, नूडल्स और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल कब्जे में ले लिए हैं ताकि लैब जांच कराई जा सके। ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पुलिस हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है। आत्महत्या, जहरीला खाना या फिर किसी साजिश के कोण से भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही और वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

दुर्गम ढलान पर मिला महाराष्ट्र से आए लापता पर्यटक का शव

हमारे संवाददाता

टिहरी। तपोवन क्षेत्र में नीरगढ़ बैंड के समीप एक व्यक्ति का शव सड़क से लगभग 40 मीटर नीचे दुर्गम ढलान पर झाड़ियों के बीच दिखाई देने की सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँचकर रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति महाराष्ट्र से अपने परिवार एवं मित्रों के साथ कुल 9 सदस्यों के समूह में ऋषिकेश घूमने आया था। इस दौरान संबंधित व्यक्ति के लापता होने पर दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को थाना लक्ष्मणझूला में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी।



एसडीआरएफ ने रोप रेस्क्यू कर सड़क तक पहुँचाया

आज तपोवन चौकी से लगभग 500 मीटर आगे नीरगढ़ बैंड के पास सड़क से नीचे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव दिखाई देने पर स्थानीय पुलिस के माध्यम

से एस को इसकी सूचना दी गई।

सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना

हुई। घटनास्थल पर पहुँचने पर टीम ने सड़क से लगभग 40 मीटर नीचे दुर्गम ढलान एवं झाड़ियों के बीच शव की स्थिति का आकलन किया। स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं ढलान की कठिनाई को देखते हुए टीम द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाते हुए रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। एसडीआरएफ द्वारा रोप रेस्क्यू तकनीक तथा स्ट्रेचर का उपयोग करते हुए अत्यंत सावधानीपूर्वक शव को दुर्गम ढलान से ऊपर सड़क तक पहुँचाया। इसके उपरांत शव को अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु तपोवन चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त भी कर ली गई है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार
समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।